

## ‘सरकार को राजनीतिक दृष्टि से भी ईमानदार व तटस्थ होना चाहिए, केवल संख्या बल से सही होना पर्याप्त नहीं’

सोनिया गांधी ने अखबार में संपादकीय लेख लिखकर, चुनाव के दौरान संसद का विशेष सत्र आहूत करने के निर्णय को चुनौती दी

कूनो नेशनल पार्क से अफ्रीकन चीता बारां के जंगलों में पहुँचा

छबड़ा, 13 अप्रैल (निसं)। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान के बारां जिले के जंगलों में पहुँचा अफ्रीकन चीता “केपी-3” इन दिनों लगातार मूवमेंट कर रहा है। सोमवार को यह चीता छबड़ा के आलमपुरा क्षेत्र में पहुँच गया। इस

■ वन विभाग छबड़ा के आलमपुरा क्षेत्र में चीता “केपी-3” के मूवमेंट पर लगातार नज़र रख रहा है।

दौरान वन विभाग टीम ने लगातार उसके मूवमेंट पर नज़र बनाए रखा।

यह चीता पार्वती नदी किनारे होते हुए यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद उसे पेड़ों की छांव में आराम करते देखा गया और उसने आसपास के क्षेत्र में हल्की चहलकदमी भी की।

क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौड़ के अनुसार, चीते की मौजूदगी की जानकारी आसपास के ग्रामीणों को हो गई थी, जिसके चलते लोग उसे देखने के लिए उसुक नज़र आए। पूरे दिन चीते की गतिविधियाँ संबंधित क्षेत्र में ही सीमित रही।

वन विभाग द्वारा लगातार सतर्कता बरती जा रही है, ताकि चीते की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। यहाँ छबड़ा रेंज के साथ-साथ एमपी के वनकर्मी भी मौजूद हैं। निगरानी के दौरान छबड़ा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## अमेरिका ने जहाजों को चेतावनी देनी शुरू की कि ब्लॉकेड शुरू हो गया है

पर चेतावनी से एक बात साफ हुई की अगर कोई भी जहाज ईरानी “ऑयल” ले जाते हुए पकड़ा गया तो उसे बमबारी से उड़ा दिया जाएगा

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 13 अप्रैल। डॉनल्ड ट्रम्प की होमरूम स्ट्रेट में नाकेबंदी की धमकी सोमवार शाम से शुरू हो गई है। यह सिर्फ शुरुआत है, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

इस बीच, ट्रम्प ने ईरान युद्ध में एक नया मोर्चा खोल लिया है। इस बार, ट्रम्प ने पोप लियो चौदहवें के साथ विवाद खड़ा किया। पोप ने पहले ट्रम्प के ईरान युद्ध की आलोचना की थी। ट्रम्प ने खुद को एक शांत तस्वीर में ईसा मसीह के रूप में प्रस्तुत किया, और इस कदम ने लाखों ईसाइयों को नाराज कर दिया।

कुछ समय से, ट्रम्प ने पोप पर तीखे हमले किए हैं, यह कहते हुए कि वह विदेशी नीति या अपराधों के मामले पर बोलने के लिए उपयुक्त नहीं है। पोप का अपमान करना ट्रम्प के लिए कूटनीतिक मुसीबत और रणनीतिक गलती साबित हो सकता है, क्योंकि होमरूम नाकेबंदी की शुरुआत के साथ उन्होंने अपने

■ पर, सवाल यह उठ रहा है कि ये जहाज अगर रूस और चीन जा रहे होंगे तो भी क्या अमेरिका उन्हें उड़ा देगा।

■ अमेरिका का यह “ब्लॉकेड” ईरान के लिए गंभीर धमकी है। क्योंकि, युद्ध के दौरान भी ईरान अपना “ऑयल” बेचकर काफी राजस्व प्राप्त कर रहा था तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे-जैसे ऑयल के दाम बढ़ने लगे। ईरान की आमदनी भी वैसे-वैसे बढ़ती जा रही थी।

■ अब यह आमदनी अगर बंद हो गई तो भारी आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। अतः ईरान ने पुतिन से बात की है, हस्तक्षेप करने के लिए।

आक्रमण को पूरी तरह से एक नए क्षेत्र में फैला दिया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि नाकेबंदी का कदम खतरों और अज्ञात जोखिमों से भरा है। किन्हीं भी कूड तेल ले जाने वाले जहाजों या उर्वरक से लदे जहाजों की नाकेबंदी, जिनकी भारी मांग है, आगे और भी टकराव को जन्म दे सकती है। पहले से ही जटिल संघर्ष और बिगड़ सकता है और अन्य देश इसमें फंस सकते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका पहले ही जहाजों को नाकेबंदी के बारे में संकेत दे चुका है। लेकिन सोचिए, अगर नाकेबंदी में चीन या रूस को कूड भेजने वाले जहाज शामिल हों, तो क्या अमेरिका उनकी यात्रा रोक सकता है? और यदि अमेरिका ने इन जहाजों को भी रोका, तो रूस या चीन की प्रतिक्रिया क्या होगी? (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## चीन ने अरुणाचल में “नामकरण” अभियान शुरू किया

भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन के इस कदम की आलोचना की और दोनों देशों के संबंधों में नकारात्मक प्रभाव डालने वाला बताया

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 10 अप्रैल। जब भारत सरकार खाड़ी संकट के संभावित और नकारात्मक आर्थिक प्रभावों में व्यस्त है, पूर्वी सीमाओं पर संकट बढ़ रहा है, क्योंकि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के जिलों, गांवों, पहाड़ों और नदियों के नाम बदलने के अभियान को फिर से जारी कर दिया है।

2025 के अंत तक, चीन ने अरुणाचल में 89 स्थानों के नाम बदलने के पांच बैच जारी किए हैं। यह प्रक्रिया 2017 में शुरू हुई और 2021, 2023, 2024 और 2025 में जारी रही। चीन अरुणाचल को जोगानान या दक्षिण तिब्बत कहता है और अरुणाचल के लगभग 83,000 से 90,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर अपना क्षेत्रीय अधिकार जताता है। इसने 1914 के

■ पूरा विश्व ईरान वॉर की समस्याओं से त्रस्त है, खासकर भारत का पूरा ध्यान पैट्रोल व एलपीजी संकट से निपटने पर है, ऐसे में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों का नया नाम रखना शुरू कर दिया है।

■ चीन ने यह कार्यवाही 2017 में शुरू की थी तथा 2017 से 2025 तक नए नामों के 5 बैच जारी कर चुका है।

■ चीन में अरुणाचल को जोगानान या दक्षिणी तिब्बत कहा जाता है। चीन ने 1914 में शिमला समझौते के तहत बनी मैकमोहन रेखा को पहले ही टुकरा दिया है और वह अरुणाचल पर दावा जताता रहा है।

शिमला समझौते में ब्रिटिश भारत और भारत के बीच स्थापित मैकमोहन रेखा को खारिज कर दिया है। चीन पश्चिमी लद्दाख में अक्सई चिन के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर भी अपने क्षेत्रीय अधिकार का दावा करता है।

चीन की इस गतिविधि पर प्रतिक्रिया देते हुए, विदेश मंत्रालय ने इसे आशंकाजनक और अमान्य माना। चीन को निर्माण करने और बड़े दावे पेश करने का “शरारती प्रयास” बताया। विदेश (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस ने विशेष सत्र के लिए व्हिप जारी किया

नई दिल्ली, 13 अप्रैल। कांग्रेस ने लोकसभा के अपने सदस्यों को व्हिप जारी करते हुए कहा है कि वे आगामी 16 से 18 अप्रैल तक होने वाली सदन की तीन दिवसीय विशेष बैठक में मौजूद रहें तथा पार्टी के रुख का समर्थन करें। कांग्रेस ने आधिकारिक बयान में कहा कि 16 से 18 अप्रैल तक

■ महिला आरक्षण अधिनियम एवं परिशीलन में जुड़े विधेयकों व संशोधनों को पेश करने के आयोजित किया जा रहा है विशेष सत्र।

लोकसभा में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार और मतदान होना है, इसलिए सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य है। पार्टी ने अपने सदस्यों के लिए यह व्हिप उस वक्त जारी किया है, जब (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## तेल, एलपीजी के बाद अब सल्फर आपूर्ति भी खतरे में

ईरान जंग का दुष्परिणाम सल्फर आपूर्ति पर भी पड़ रहा है, जो कि खाद, बैटरी, सेमीकंडक्टर के निर्माण में महत्वपूर्ण है

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 13 अप्रैल। जब घर-घर ईंधन की कीमतों और एलपीजी की आपूर्ति को लेकर चिंता है, तब ईरान युद्ध के बीच, एक और धीमा, लेकिन गंभीर व्यवधान पृष्ठभूमि में उभर रहा है। यह व्यवधान सल्फर से जुड़ा है, जो उर्वरक, बैटरी, रसायन, धातु और यहां तक कि सेमीकंडक्टर के लिए एक आवश्यक मूल तत्व है।

यूरिया से लेकर कंप्यूटर चिप तक, सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन लाइनों के लिए अनिवार्य है। हालाँकि, होमरूम स्ट्रेट के आसपास यह व्यवधान आपूर्ति में झटका पैदा कर रहा है, जो कारखानों के उत्पादन को धीमा कर सकता है और खाद्य कीमतों को बढ़ा सकता है।

मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार, समुद्र में भेजी जाने वाली सल्फर का आधा भाग होमरूम

■ सल्फर की आपूर्ति बाधित हुई तो भारत में सरकार पर खाद सिस्टी का अतिरिक्त भार पड़ेगा, किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिलेगी, खाद्यान्न महंगा हो जाएगा और रसायन व धातु निर्माण संयंत्रों की लागत भी बढ़ जाएगी।

■ मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट के अनुसार, विश्व भर में सल्फर की कुल आपूर्ति का 50 प्रतिशत होमरूम से गुजरता है और 28 फरवरी के बाद से 44,000 कंपनियों के “शिपमेंट” अवरूद्ध हो चुके हैं।

स्ट्रेट से होकर गुजरता है। इन हैड ब्रैंड स्ट्रीट की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, वॉर शुरू होने के बाद से 44,000 कंपनियों का एक एक शिपमेंट प्रभावित हुआ है।

सल्फर मुख्य रूप से तेल और गैस परिष्करण का बाय प्रॉडक्ट है। वैश्विक निर्यात का 45 प्रतिशत से अधिक खाड़ी देशों के पास है। मूल रूप से, किसी भी तेल व्यवधान का असर जल्दी ही

सल्फर आपूर्ति पर पड़ता है।

दुनिया भर की सल्फर की कुल मांग का लगभग 60 प्रतिशत उर्वरकों से आती है। बाकी का इस्तेमाल रसायन, धातु प्रसंस्करण, बैटरी और चिप निर्माण में होता है।

भारत अपनी सल्फर आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आयात करता है, मुख्यतः यूरिया और फॉस्फेट उर्वरकों के लिए। किसी भी लंबी अवधि

का व्यवधान भारी प्रभाव दिखा सकता है, जैसे सरकार के लिए उर्वरक सब्सिडी का बोझ बढ़ना, किसानों के लिए उच्च इनपुट लागत, आपूर्ति संघन होने पर खाद्य महंगाई का खतरा, रसायन और धातु उत्पादकों के लिए लागत में वृद्धि।

ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडोनेशिया, जो कि प्रमुख निकल उत्पादक है, अपनी सल्फर का लगभग 75 प्रतिशत मध्य पूर्व से आयात करता है। भारत भी उर्वरक से जुड़ी मांग के लिए इसी तरह की निर्भरता में बैठा है। इसलिए, ईरान संघर्ष लंबा चलता है तो यह दबाव बना रहता है। वास्तव में, द सौफान सेंटर और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) द्वारा किए गए हालिया शोध और विश्लेषण में निष्कर्ष निकला है कि उर्वरक आपूर्ति में व्यवधान जल्दी ही खाद्य सुरक्षा जोखिम में बदल सकता है।

भारत अपनी सल्फर आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आयात करता है, मुख्यतः यूरिया और फॉस्फेट उर्वरकों के लिए। किसी भी लंबी अवधि

## बंगाल में एक्शन मोड़ में है ईडी

-जाल खंबाता-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 13 अप्रैल। एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एजेंसी ने कई घोटालों से जुड़े उच्च प्रोफाइल छापों और संपत्ति जब्तियों की श्रृंखला शुरू की है, जिनमें भर्ती घोटाला, जमीन

■ राज्य में ईडी ने कई घोटालों की लिस्ट बनाई है और उसके आधार पर तृणमूल नेताओं व सरकार के अफसरों पर धड़ाधड़ रैड कर रही है।

हड़पना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के गेहूँ का गबन शामिल है।

मार्च के अंत और अप्रैल 2026 की शुरुआत में हुई गतिविधियों की तूफानी श्रृंखला में, केन्द्रीय एजेंसी ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## ‘अगर जीत का मार्जिन, काटे गए वोटर्स की संख्या से कम है तो हम हस्तक्षेप करेंगे’

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में एसआईआर के संबंध में दायर याचिकाओं के बारे में हो रही सुनवाई के दौरान बहुआयामी टिप्पणी की

-जाल खंबाता-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 13 अप्रैल। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने केवल पश्चिम बंगाल में ही एसआईआर के दौरान संदिग्ध मतदाताओं को “ताकिक असंगति” सूची बनाई।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने यह टिप्पणी की और कहा कि अब पश्चिम बंगाल में मतदाता विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों के बीच फंस गए हैं।

न्यायमूर्ति बागची ने यह टिप्पणी उस समय की, जब चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि आयोग के नोटिसों का निर्णय करने वाले न्यायिक अधिकारियों के कुल मामलों का 47 प्रतिशत खारिज किया गया।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, “यह अंतिम साधन को न्यायसंगत बनाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि साधन अंत को

न्यायसंगत बनाने के लिए है। यह राज्य और चुनाव आयोग के बीच कोई संघर्ष नहीं है। यह आरोप-प्रत्यारोप का खेल भी नहीं है। यह तो मतदाता के दो पादों के बीच फंसने का मामला है। अदालतों ने केवल चुनाव को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप किया है, रोकने के लिए नहीं।”

लेकिन न्यायमूर्ति बागची ने यह भी कहा कि जब तक “अत्यधिक संख्या में मतदाता (मतदान से) बहिष्कृत नहीं होते,” चुनाव के परिणामों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा, “यदि 10 प्रतिशत मतदाता वोट नहीं करते और जीत का अंतर 10 प्रतिशत से अधिक है, तो... यदि यह 5 प्रतिशत से कम है तो हमें विचार करना होगा। पहले किसी

■ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि बंगाल में वोटर, संसदीय अर्थोरीटीज चुनाव आयोग व राज्य सरकार के बीच में पिस रहा है। अतः सुप्रीम कोर्ट इस सिद्धांत के अनुरूप काम कर रहा है कि चुनाव करने को प्रोत्साहित करना चाहिए, चुनाव रद्द करने को नहीं।

■ अतः, अगर 10 प्रतिशत वोटर, वोट नहीं कर पाए तथा उदाहरण के लिए जीत का मार्जिन कम, पाँच प्रतिशत, है तो हम हस्तक्षेप करेंगे।

उम्मीदवार को अपील न्यायाधिकरण के सामने प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि किसी उम्मीदवार को चुनाव में भाग लेने के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता। कृपया यह न सोचें कि हम यह नहीं सोच रहे कि बहिष्कृत

उन्होंने कहा, “हमने संवैधानिक प्राधिकरण को मतदाता सूची को शुद्धता के मुद्दे में जाने की अनुमति दी है। आपके एसआईआर पर आपकी मूल ईसीआई अधिसूचना ने 2002 की सूची को नहीं छुआ। लेकिन आपकी ताकिक असंगति सूची अस्वीकरण का कारण 2002 की सूची आदि है। आपकी अधिसूचना उन लोगों को प्रभावित करती है, जो 2002 की सूची से संबंधित हैं, अर्थात् 2002 की सूची मानक है। अंतिम सूची में आपने 2002 की सूची के सदस्यों को नहीं हटाया। जब बिहार एसआईआर पर विचार हुआ, तो आयोग की प्रस्तुतियाँ स्पष्ट थीं कि 2002 की सूची के सदस्यों को कोई हस्ताक्षर देने की आवश्यकता नहीं है। कृपया बिहार के मामले में

मतदाताओं का क्या होगा।”

न्यायमूर्ति बागची ने पश्चिम बंगाल और बिहार में एसआईआर के बीच भिन्नताओं पर भी प्रकाश डाला, विशेषकर ताकिक असंगति सूची के निर्माण में।

## ‘तृणमूल अलगाववादियों का समर्थन करती है’

-जाल खंबाता-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 13 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते

■ प्रधानमंत्री मोदी ने सिलीगुड़ी में एक सभा में कहा, चिकन्स नैक को काट कर उत्तर पूर्व को भारत से अलग करने की धमकी देने वाली टुकड़े-टुकड़े गैंग का तृणमूल समर्थन करती है।

हुए कहा कि सिलीगुड़ी और उसके आसपास का क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और राज्य की सत्ताधारी पार्टी को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)